30 मार्च, 1993 को की गई थी। अतः वर्ष 1991–92 और 1992–93 से संबंधित अपेक्षित ब्यौरा शून्य है। वर्ष 1993–94 में, भोपाल जिले में सैल्फ-एम्पलायड वीमेंस एसोसिएशन, भोपाल नामक एक संगठन को लगभग 2250 महिला ऋणप्राप्तकर्ताओं को आगे उधार देने के लिए 25–50 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया।

(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत, अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए बचत और ऋण के क्षेत्रों में लगे गैर-सरकारी संगठनों को ऋण स्वीकृत किया जाता है।

(ग) महिला लाभप्राप्तकर्ताओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

महिला लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या (राज्यवार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	महिला लाभ-प्राप्तकर्ताओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	14872
2.	बिहार	2500
3.	कर्नाटक	2020
4.	केरल	6670
5.	मध्य प्रदेश	2250
6.	महाराष्ट्र	5695
7.	मणिपुर	2000
8.	उड़ीसा	780
9.	राजस्थान	1605
10.	तमिलनाडु	18583
11.	उत्तर प्रदेश	2097
12.	पश्चिम बंगाल	3250
	योग :	62322

विशेष शिक्षा नीति

2900. **श्री राजनाथ सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा वर्ष 1994–95 के लिए एक विशेष शिक्षा नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शिक्षा के स्तर में गिरावट आने के क्या कारण हैं और शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में सरकार द्वारा शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए आपरेशन ब्लैकबोर्ड (ओ.बी.), गैर औपचारिक शिक्षा (एन.एफ.ई.), शिक्षक शिक्षा और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजनाएं हैं। सभी स्तरों पर शिक्षा की विषयवस्तु व प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए कई और उपाय भी किए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं–पाठ्यचर्या का नवीकरण, पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल में सुधार लाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसके अलावा, देश की सभी तकनीकी संस्थाओं को संसद द्वारा सृजित एक संविधिक निकाय-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआई सीटीई) द्वारा निर्धारित मानदंडों की अभिपुष्टि करना होता है। तकनीकी और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा

देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने हाल में एक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रत्यायन परिषद् का गठन किया है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसी प्रकार की संस्था का उच्च शिक्षा के लिए गठन किया है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

2901. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में सरकार की नीति क्या रही है ;

(ख) क्या वर्तमान विश्वविद्यालयों को दो भागों में बांटने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) केन्द्रीय विद्यालय योजना मुख्यतया केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है । तदनुसार, केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या वाले स्थानों पर और साथ ही उन मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं, जो प्रायोजक एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती है ।

केन्द्रीय विद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के आवासीय परिसरों में भी खोले जाते हैं जहां प्रायोजक परियोजना विद्यालय संबंधी आवर्ती और अनावर्ती व्यय वहन करने के लिए सहमत होते हैं ।

सरकार ने वर्ष 1993-94 से 1997-98 के दौरान रक्षा/सिविल क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 20 केन्द्रीय विद्यालय और परियोजना क्षेत्र में यथासंभव केन्द्रीय विद्यालयों के खोलने का अनुमोदन किया है ।

(ख) और (ग) सरकार को इस प्रकार के किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है ।

गुजरात में शारीरिक शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता दिया जाना

2902. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता आवंटित/जारी की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल

2903. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की कमी है ;

(ख) क्या सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की आवश्यकता का आकलन किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और